eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 02, February 2026

भारत की समावेशी विकास रणनीतियाँ

डॉ0 अशोक कुमार[1]
[1]असिस्टेन्ट प्रोफेसर–अर्थशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय, मिश्रिख, सीतापुर उ0प्र0

Received: 20 Feb 2026 Accepted & Reviewed: 25 Feb 2026, Published: 28 Feb 2026

Abstract

सामान्यतया समावेशी विकास का अर्थ है देश की समस्त आबादी –गरीब, महिला एवं वंचित वर्ग को विकास की प्रक्रिया में शामिल करना और सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। दूसरे शब्दों में यह विकास के लाभों को देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचाने का उपक्रम है। इसके अन्तर्गत आर्थिक विकास ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, अवसरों की समानता, शिक्षा एवं स्वास्थ्य तक पहुँच और जीवन स्तर में सुधार के साथ पूर्ण गरिमा युक्त मानव जीवन प्रदान करने का लक्ष्य रखा जाता है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में विकास तभी सार्थक माना जा सकता है जबकि यह समावेशी हो। प्रस्तुत शोध पत्र भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज वाले देश के लिए उपयोगी समावेशी विकास रणनीतियों की पड़ताल करेगा।

कीवर्ड–समावेशी, विविधतापूर्ण, टपकन, वंचित, कार्यशील, समतामूलक, नामांकन अनुपात, जीवन प्रत्याशा।

Introduction

समावेशी विकास का विचार वैश्विक स्तर पर विशेष रूप से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रस्तुत Inclusive Development Index (IDI) के माध्यम से सामने आया। विकास के शुरूआती चरणों में सभी अर्थशास्त्री माइकल टोडैरो के टपकन सिद्धान्त (Trickle Down Effect) में विश्वास करते थे। उनका विश्वास था कि विकास के प्रारंभिक चरणों में विकास रूपी फल के लाभ भले ही गरीब एवं वंचित तबके तक न पहुँचे परन्तु लगातार प्राप्त की गयी उच्च संवृद्धि के लाभ धीरे–धीरे रिसाव के माध्यम से अर्थव्यस्था के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक अवश्य पहुँचते हैं। कई दशकों तक अर्थशास्त्रियों का टोडैरो के इस सिद्धान्त में विश्वास रहा परन्तु विश्लेषण करने पर यह तथ्य लगातार सामने आये कि संवृद्धि एवं विकास के लाभ आम लोगों को प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। अतः सभी अर्थशास्त्रियों ने रिसाव या टपकन सिद्धान्त की जगह समावेशी विकास को वरीयता दी। आज उसी अर्थव्यवस्था के विकास स्तरों की प्रशंसा होती है जिसने समावेशी विकास की अवधारणा को साकार करते हुए विकास किया हो। संयुक्त राष्ट्र संघ ने Sustainable Development Goals (SDGs) के लिए भी "Leave No One Behind" का सिद्धान्त दिया है जो कि समावेशी विकास की वैश्विक अवधारणा के अनुकूल है। भारत ने भी इन वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप अनेक नीतियाँ और कार्यक्रम लागू किये हैं जिनका उद्येष्य आर्थिक संवृद्धि को सामाजिक समानता से जोड़ना है।

समावेशी विकास आर्थिक अवसरों के व्यापक वितरण, आय असमानता में कमी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य तक सार्वभौमिक पहुँच तथा सामाजिक एवं राजनीतिक सशक्तीकरण की विस्तृत अवधारणा को व्यक्त करता है। यह अवधारणा मानव विकास सिद्धान्त (Human Development Theory) से जुड़ी है जिसे अमर्त्य सेन ने "Capability Approach"के माध्यम से प्रतिपादित किया है। अमर्त्य सेन के अनुसार विकास का उद्येष्य केवल आय वृद्धि नहीं बल्कि व्यक्तियों की क्षमताओं (Capabilities) का विस्तार है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 02, February 2026

स्वतंत्रता के बाद भारत ने नियोजित विकास मॉडल अपनाया और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से औद्योगीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार और भूमि सुधारों द्वारा संसाधनों के न्यायसंगत वितरण का प्रयास किया गया। 1960–70 के दशकों में हरित क्रांति ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की किन्तु इसके कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित होने के कारण अनेक क्षेत्रीय असमानताएं भी उत्पन्न हुईं। 2000 के दषक में MNREGA और 06 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम ने सामाजिक सुरक्षा और मानव पूंजी सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दी। हाल के वर्षों में नीति आयोग द्वारा SDG आधारित नीति ढांचा, जन–धन जैसी वित्तीय समावेशन योजनाओं, डिजिटल इंडिया, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के विस्तार ने भारत के विकास को अधिक लक्षित एवं व्यापक बनाने का प्रयास किया है। इस प्रकार भारत में समावेशी विकास की अवधारणा समय के साथ राज्य नियोजित मॉडल से बाजार संचालित व्यवस्था और अंततः मानव केंद्रित एवं सतत विकास की ओर क्रमिक रूप से विकसित हुई ।

विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2018 में जारी 'समावेशी विकास सूचकांक–2018' के अनुसार विश्व की उदयीमान अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान 62 वां था जिसे संतोषजनक नहीं माना जा सकता। भारत में सबसे अमीर 01 प्रतिशत लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40 प्रतिशत है। जबकि शेष आबादी के पास कुल संपत्ति का 01 प्रतिशत है। संपत्ति का यह असमान वितरण यह दर्शाता है कि भारत में होने वाले विकास का लाभ अधिकांश आबादी तक नहीं पहुँच पा रहा है। यद्यपि खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसे कार्यक्रमों से 80 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं फिर भी धन–संपत्ति का वितरण असमान रूप से विषम बना हुआ है जो समतामूलक समृद्धि के लिए प्रणालीगत बाधाओं को उजागर करता है। भारत में समावेशी विकास में एक बड़ी बाधा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का प्रभुत्व है। यह भारत के कुल कार्यबल का 90 प्रतिशत है। इन श्रमिकों को उचित वेतन, औपचारिक रोजगार लाभ और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती है। वास्तविक समावेशन के लिए इस विशाल कार्यबल को औपचारिक बनाने और बुनियादी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्रम कानूनों में सुधार पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता होगी। भारत में विभिन्न राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में अंतर होने के कारण गरीब राज्य अपने राज्य में बुनियादी अवसंरचना और सामाजिक सेवाएं नहीं प्रदान कर पाते हैं जिससे समावेशी विकास बाधित होता है। विश्व असमानता रिपोर्ट–2026 के अनुसार महिलाएं जो कि कार्यशील जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं पुरूषों की तुलना में प्रत्येक घंटे के काम के लिए केवल 32 प्रतिशत आय अर्जित करती हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स–2025 के अनुसार विश्व के 148 देशों में भारत 133 वें पायदान पर है जिससे यह पता चलता है कि महिलाओं के लिए रोजगार और ऋण की पहुँच अभी सुनिष्चित नहीं हो पा रही है। मूलभूत अवसंरचना सुविधाएं जैसे बिजली, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि का अभी तक भारत में सार्वभौमीकरण नहीं हो पाया है। इन मूलभूत जीवनाधार सुविधाओं का अभाव समावेशी विकास को अत्यंत गहरे से बाधित करता है।

उपर्युक्त तथ्य यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि भारत में समावेशी विकास को उस रूप में धरातल पर नहीं लाया जा सका है जिससे अर्थव्यवस्था के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी विकास रूपी फल के लाभ प्राप्त हो सकें। समावेशी विकास के लिए भारत की प्रमुख रणनीतियां निम्नवत ली जा सकती हैं–

1. आर्थिक समावेशन– समावेशी विकास के लिए आर्थिक समावेशन नीतियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह किसी भी अर्थव्यवस्था में समावेशन सुनिश्चित करने का सबसे महत्वपूर्ण एवं सषक्त माध्यम है। ग्रामीण

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 02, February 2026

महिलाओं के लिए आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूह (SGHs) के माध्यम से कौशल वृद्धि, पूंजी और बाजार पहुँच में सहायता प्रदान की जा रही है। इसी प्रकार MGNREGA (Viksit Bharat-Gurantee for Rozgar and Ajeevika Mission-VB-G RAM G) Act 2025 योजना के तहत वर्ष 2024 में 220.11 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजित किया गया। MSME क्षेत्र को अनेक प्रकार की वित्तीय सुविधाएं एवं कर छूटें प्रदान करके इसे सशक्त किया गया है जिससे अर्थव्यवस्था में रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि दृष्टिगत हुई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना (Direct Benefit Transfer-DBT Scheme) आदि वित्तीय समावेशन योजनाओं से भारतीय जनसमुदाय के आर्थिक समावेशन का प्रयास लगातार जारी है।

2. सामाजिक समावेशन–समावेशी विकास के लिए आर्थिक समावेशन के साथ ही सामाजिक समावेशन भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। सामाजिक समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया जाने वाला सबसे प्रभावी कार्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान रहा है। इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लाखों घरों में शौचालय निर्मित हुए हैं जिससे स्वास्थ्य में सुधार तथा सामाजिक गरिमा में वृद्धि हुई है। इसी के साथ भारत में दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य भारत अभियान नामक कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है जिसके तहत दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए सरकार सरकारी भवनों एवं सार्वजनिक परिवहन में विशेष सुविधाएं प्रदान कर रही है। समावेशी विकास के लिए देश के विभिन्न राज्यों के बीच व्याप्त असमानताओं को समाप्त करने के लिए नीति आयोग द्वारा अभिलाषी जिला कार्यक्रम अत्यन्त ही महत्वपूर्ण रहा है। इसके तहत देश उन जिलों को प्राथमिकता प्रदान की गयी जिनकी विकास दर अन्य जिलों से कम रही थी। UNDP ने भी भारत के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की प्रशंसा की है तथा इसे क्षेत्रीय विकास असमानताओं को समाप्त करने के लिए अत्यन्त ही प्रभावी बताया है।

3. शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुधार–शिक्षा एवं स्वास्थ्य को समावेशी विकास का केन्द्रीय तत्व माना गया है। विभिन्न शिक्षा के स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात, जीवन प्रत्याषा, शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर जैसे संकेतक किसी भी अर्थव्यस्था के समावेशी विकास को पुष्ट करने वाले संकेतक हैं। मानव विकास सूचकांक–2025 के अनुसार विश्व के 193 में देशों में भारत की रैंक 130 रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीवन प्रत्याशा 72 वर्ष हो गयी है। यह निश्चित ही भारत में चलायी जा रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत योजना, जननी सुरक्षा योजना और पोषण अभियान का सुखद परिणाम है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्कूलिंग के प्रत्याषित वर्षों (India's Expected Years of Schooling) में वृद्धि हुई है और अब भारत में बच्चे लगभग 13 वर्ष व्यतीत कर रहे हैं। निष्चित रूप से शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009, समग्र शिक्षा अभियान और नई शिक्षा नीति–2020 के द्वारा यह संभव हो पाया है जिस पर लगातार आगे बढ़ते जाने की आवश्यकता है।

Key Data (HDI)	2020	2024	2025
Rank	131	13	130
Life Expectancy	67.2	67.7	72
Expected Years of Schooling	12.1	12.6	13

*डाटा स्रोत: HDI Report of Different Years

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 02, February 2026

मानव विकास सूचकांक–2025 की रिपोर्ट भारत के संदर्भ में एक विशेष तथ्य का जिक्र करती है। यह रिपोर्ट बताती है कि भारत में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी असमानताएं भारत के प्रभावी मानव विकास सूचकांक को कम करती हैं। रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य और आय असमानताएं भारत के मानव विकास सूचकांक में लगभग 30 प्रतिशत की कमी लाते हैं।

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रो0 अमर्त्य सेन के कैपाबिलिटी एप्रोच (Capability Approach) को समावेशी विकास का आधार कहा जा सकता है। कैपाबिलिटी एप्रोच के प्रमुख तत्वों में प्रो0 अमर्त्य सेन ने निम्न को लिया है–

1–आय वृद्धि

2–शिक्षा एवं स्वास्थ्य तक पहुँच

3–सामाजिक सुरक्षा

4–संस्थागत सशक्तीकरण

प्रो0 सेन के अनुसार यदि विकास आम लोगों के लिए उपर्युक्त चार तत्वों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर पाता तो इसे समावेशी नहीं कहा जा सकता।

Development=Functionings+Capabilities+Freedom

प्रो0 सेन के उपर्युक्त सूत्र के अनुसार यदि आय में वृद्धि के बावजूद आम लोग उपलब्ध अवसरों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, आय में वृद्धि के बावजूद उसकी क्षमताएं सीमित हैं और आय में वृद्धि के बावजूद लोगों की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रताओं में वृद्धि नहीं हो पा रही है तो यह समावेशी विकास नहीं कहलायेगा।

हालांकि कैपाबिलिटी एप्रोच के द्वारा समावेशी विकास का मापन कठिन है। परन्तु यह एक सशक्त सैद्धान्तिक आधार अवश्य है जिसके आधार पर अर्थव्यवस्था के समावेशी विकास स्तर को समझा जा सकता है। इस एप्रोच के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर विचार करने पर हम पाते हैं कि भारत में समावेशी विकास को अधिक प्रभावी बनाने के लिए भविष्य में प्रभावी प्रयास जारी रखने होंगे।

संदर्भ सूची–

1.Amartya Sen, 1999, Development as Freedom, Oxford University Press
2.International Labour Organisation, 2023, World Employment and Social Outlook https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@inst/documents/publication/wcms_865332.pdf
3.Niti Aayog, 2023, SDG India Index Report, Government of India https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2024-07/SDG_India_Index_2023-24.pdf
4.Reserve Bank Of India Annual Report, 2023 https://www.rbi.org.in/Scripts/AnnualReportPublications.aspx?year=2023
5.https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2020
6.https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2023-24
7.https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2025
8.https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2025/
9.https://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2018.pdf